भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : **54**
गुरुवार, 28 नवंबर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

धनबाद विमानपत्तन का पुनरुद्धार

***54. श्री दुलू महतोः**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने धनबाद विमानपत्तन के पुनरुद्धार के लिए कोई कार्य योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) धनबाद विमानपत्तन के पुनरुद्धार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त विमानपत्तन के विकास अथवा पुनरुद्धार में निजी कम्पनियों को शामिल करने अथवा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) धनबाद विमानपत्तन के पुनरुद्धार में विलम्ब के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"धनबाद विमानपत्तन का पुनरुद्धार" के संबंध में श्री दुलू महतो द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 28.11.2024 के मौखिक प्रश्न सं. 54 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ) : क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक), भारत में, विशेष रूप से दूरदराज और अल्पपरिचालित क्षेत्रों में अवसंरचना और संपर्क में सुधार के लिए सरकार समर्थित पहल है। 'उड़ान' एक अविरत योजना है, जिसमें योजना के अंतर्गत अधिक गंतव्यों और मार्गों को शामिल करने के लिए समय-समय पर बोली प्रक्रिया आयोजित की जाती है। अपरिचालित और अल्पपरिचालित हवाईअड्डों का पुनरुद्धार/उन्नयन वैध बोली के माध्यम से उनकी पहचान करके और चयनित एयरलाइन ऑपरेटर (एसएओ) को अवॉर्ड किए जाने के बाद किया जाता है।

झारखंड राज्य सरकार के स्वामित्व वाली धनबाद हवाईपट्टी, उड़ान दस्तावेज़ में अपरिचालित हवाईपट्टियों की सूची में उपलब्ध है।

'उड़ान' योजना के 5.2 चरण के दौरान 20 सीट से कम क्षमता वाले छोटे विमानों के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं, जो झारखंड के धनबाद हवाईअड्डे को जोड़ेगी।

तत्पश्चात, झारखंड राज्य सरकार से छोटे विमान (2बी) के प्रचालन और भविष्य में श्रेणी 3सी में विस्तार के लिए भूमि की उपलब्धता के संबंध में अपनी सहमति और पुष्टि प्रदान करने का अनुरोध किया गया। राज्य सरकार ने भूमि संबंधी बाधाओं के कारण धनबाद हवाईअड्डे के विकास के लिए अपनी सहमति नहीं दी है।